

संपादकीय

ढहते पुलों का बिहार

यह बिहार में ही हो सकता है। किसी अन्य राज्य में अपवाद के तौर पर हादसा हो सकता है। बिहार के सारण (रा) और सीवान में 24 घंटे के दौरान पांच पुल ध्वस्त हुए हैं। संभवतः आवाही, नालायकी और भ्रष्टाचार का यह विश्व कीतिमान है। एक गाड़ी के दौरान 12 पुल ध्वस्त होकर 'मलबा' हुए हैं। यह सिर्फ बिहार में ही है। इन पुलों के जरिए कितने गांव, कस्बे और मानवीय आवादी जुड़ी हुई हैं। वे सब अधर में लटक गए हैं। उनकी आवाजाही, काम-धंधों पर विराम लगाया है। एक पुल कितने समय में बनता है और उस पर कितने करोड़ खर्च किए जाते हैं, अचानक वह भरभुरा कर ढह जाता है, तो कितने धन बर्बाद होते हैं? एक जंगलराज अतीत में था और अब 'सुशासन राज'

बिहार के सारण (छपरा) और सीवान में 24 घंटे के दौरान पांच पुल ध्वस्त हुए हैं। संभवतः लापरवाही, नालायकी और भ्रष्टाचार का यह विश्व कीर्तिमान है। एक पखवाड़े के दौरान 12 पुल ध्वस्त होकर 'मलबा' हुए हैं। यह सिफ़ बिहार में ही हुआ है। इन पुलों के जरिए कितने गांव, करखे और मानवीय आबादी जुड़ी होगी। वे सब अधर में लटक गए हैं। उनकी आवाजाही, काम-धंधों पर विराम लग गया है। एक पुल कितने समय में बनता है और उस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, अचानक वह भुरभुरा कर ढह जाता है, तो कितने संसाधन बर्बाद होते हैं? एक जंगलराज अतीत में था और अब 'सुशासन राज' के ढाल पीटे जाते हैं, जो दरअसल जंगलराज ही है। अब ये 12 पुल कब तक बन सकेंगे और उनके लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, यह सवाल इसलिए किया जा रहा है, वैयक्ति बिहार मौजूदा विष वर्ष में केंद्र सरकार की 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि पर गुजारा कर रहा है। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार समेत सत्ता और विषक्ष के सभी बड़े नेता 'विशेष राज्य का दर्जा' दिए जाने का प्रलाप करते रहे हैं। हाल ही में सत्तारुद्ध जनता दल-यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई थी। उसमें भी यह प्रस्ताव पारित किया गया।

सरकार की स्थिरता के आधार हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीते कल ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर विशेष अर्थिक सहायता मांगी है। बहरहाल बिहार के संदर्भ में व्यापक चिंतन-मनन करना चाहिए, क्योंकि उसे बजट के तहत जो राशि आवंटित की जाती रही है, वह भी 'अनखर्च' रहती है। दरअसल बिहार में संस्थानगत क्षमता, आधारभूत ढांचे, बाजार, उद्यमी कौशलता और उपयुक्त औद्योगिक माहौल आदि की कमी रही है, लिहाजा राशियां 'अनखर्च' रहती हैं। वित्त वर्ष 2023 में बिहार में राजस्व खर्च का 51,722 करोड़ रुपए और पूंजी बजट का 24 फीसदी, 14,786 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए जा सके। वित्त वर्ष 2020, 2021 और 2022 में भी क्रमशः 78,122 करोड़, 75,926 करोड़ और 70,083 करोड़ रुपए 'अनखर्च' ही रहे। ये कोई सामान्य और कम राशियां नहीं हैं। यदि राशि बजट की अवधि के दौरान खर्च नहीं की जाती, तो उसे त्याग देना पड़ता है। यह भी एक किस्म का आत्मसमर्पण होता है। ये राशियां 'विशेष श्रेणी के राज्य' का दर्जा मिलने के बाद जो फंड मिलता है, उनसे भी अधिक है। जब विभाग बजटीय आवंटन की राशि को खर्च करने में अक्षम है, तो उसके साफ मायने हैं कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। बिहार की बुनियादी समस्याएं हैं, जो पुलों के ढहने में ही नहीं दिखतीं, बल्कि स्कूल-कॉलेज, अस्पताल आदि भी जर्जर अवस्था में हैं। पुल किसी भी सरकार ने बनाए हों, उनके निर्माण का ऑडिट होना चाहिए।

କୁଣ୍ଡ

अलग

चर्चा में रहना जरूरी है...

शाम को एक क्लब में मेरे साथ दो दो घूंट भरते हुए एक शायर मित्र कह रहे थे कि 'अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।' मैंने उन्हें कहा कि जिंदा नजर आने के लिए चर्चा में भी रहना जरूरी है। वरना इस दुनिया में कौन पूछता है कि कौन जिंदा है और कौन मर्दा है? उस शायर मित्र ने कहा कि चर्चा में कैसे रहा जा सकता है? दो चार शेरे¹ र लिखकर तो चर्चा में नहीं रहा जा सकता। मैंने कहा सीधा सा फंडा है। कुछ ऐसे कर्म करो कि सरकारी एजेंसियां आपकी खिदमत में नजर आएं। आपके घर द्वारा पर तशरीफ लाएं। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप जब्त करके अपने साथ ले जाएं। नोट गिनने की मशीन भी साथ लेकर आएं। फिर नोट गिनते गिनते मशीन हाँफ जाए। मशीनों का कैरेक्टर संदेह के घेरे में आ जाए। लोग मशीनों की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाएं। पूछें कि ये कैसी मशीनें हैं जो नोट गिनते गिनते गर्म हो गर्हँ। मशीनें कंट्रोवर्सी में आएंगी तो यकीनन आप भी चर्चा में आएंगे। आपका धरती में आना सार्थक हो जाएगा। आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा। आप गर्व के साथ कहोगे कि मेरे नाम का डंका बजता है। मेरे घर पर कोई और आए न आए, लेकिन ईडी आती है। मेरा नाम अखबारों में छपता है। घरों में चर्चा होती है कि इनके घर में ईडी आई थी। पड़ोसी मुझे ईस्त्रा की निगाह से देखने लगते हैं। फिर ईडी के बाद सीबीआई आती है। मेरे रेपुटेशन को चार चांद लग जाते हैं। मीडिया वाले मेरे घर के बाहर कैमरे लेकर जमा हो जाते हैं। वह मुझे पूछते हैं कि पहले आपके घर में ईडी आई थी और अब सीबीआई आई है। आपने यह गौरव कैसे हासिल किया। इधर आपके मोहल्ले में कुछ कमचारी भी रहते हैं। कुछ कामगार भी रहते हैं। कुछ रिक्षा चालक भी रहते हैं। उनके घर को ईडी और सीबीआई ने गौरवान्वित क्यों नहीं किया? उनके साथ इतना भेदभाव क्यों हुआ? क्या ऐसे लोगों ने बेकार में धरती में जन्म लिया है? कैमरे की लाइटें मेरे चेहरे पर चमकने लगती हैं। कुछ चैनल वाले तो लाइव प्रसारण पर आ जाते हैं। मैं ऑनलाइन पब्लिक को दिखने लगता हूं। मेरे रिस्टेदार, मेरे दोस्त मुझे इस तरह चैनलों की भीड़ के बीच में घिरा देखकर अपने यारों दोस्तों को फोन लगाते हैं कि देखो, 'बंदे की जबरदस्त चर्चा हो रही है इसके घर में ईडी भी आई है और सीबीआई भी आई है। अब यह बंदा छोटे से घर में नहर्ह रहेगा। इसे ऐसे बड़े घर में लेकर जायाएगा, जहां नेता भी रहते हैं, अधिनेता भी रहते हैं। चोर भी रहते हैं, उचके भी रहते हैं और बाहुबली भी रहते हैं और सस्पेंड हुए अफसोसी भी रहते हैं। यानी बड़ा टाइप घर कई बर्डी हस्तियों का संगम स्थल है और यहां जो किस्मत वाले आते हैं, उनकी बाकायद अखबारों में फोटो छपती है। जिसने यहां कई डुबकी लगा ली और चंद रोज यहां बित दिए, पब्लिक की नजर में हीरो हो जाते हैं उनके आगे बड़े-बड़े देशभक्त जीरो हो जाते हैं।' हमारी बातचीत सुन रहे साथ के टेब्ल घर में बैठे एक पत्नी पीड़िता सज्जन ने बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि, 'चर्चा में रहने के लिए घर में ईडी और सीबीआई का आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आज कोई न कोई बाबा बनकर भी चर्चा में रहा जा सकता है। और बाबा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी धार्मिक प्रवृत्ति रही हो। आप यौन उत्पीड़न और बलात्कार के केस ज्ञेलते हुए जेल में रहने के बाद सबूत के अभाव में बर्बाद होकर फिर से नौकरी ज्ञाइन करके, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सूट बूट और चश्मा लगाकर प्रवचन देते हुए भी हजारे लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं। फिर प्रवचन करते हुए कायदे कानून की धजियर उड़ाते हुए भगदद्द में सैकड़ों लोगों की जान लेकर भी चर्चा में रह सकते हैं। आप पूलिस की कार्रवाई से बचने के लिए फरार होकर भी चर्चा में रह सकते हैं। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और अगर जिंदा हो तो चर्चा में रहना भी जरूरी है।

शहरों में गांवों की तुलना में अधिक साधन, सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा दूसरे शब्दों में आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं

गांवों से पलायन एवं बढ़ते शहरीकरण के खतरे

भारत में बढ़ता शहरीकरण भले ही विकास का आधार हो, लेकिन इसने अनेक समस्याओं

ललित गर्ग

बढ़ता शहरीकरण केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिये एक बड़ी चुनौती बन रहा है। वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी में से 56 प्रीसदी आबादी शहरों में रहने लगी है। गांवों से शहरों की ओर प्रलयन हो रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक शहरी आबादी अपने वर्तमान आकार से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने एवं नया भारत-विकासित भारत बनाने के लिये शहरीकरण पर बल दिया जा रहा है। एक विडम्बनापूर्ण सोच देश के विकास के साथ जुड़ गयी है कि जैसे-जैसे देश विकसित होता जायेगा वैसे-वैसे गांव की संरचना टूटती जायेगी।

दृष्टि कोण

हाथरस में एक सत्संग समारोह में हुआ, दर्दनाक हादसा बताता। दरअसल धार्मिक आयोजन में अव्यवस्था या फर्जी बाबाओं की हेगफेरी तक सीमित नहीं है यह घटनाक्रम। यह हादसा देश के विकास की तस्वीर की हकीकत भी बयान करता है। हाथरस में भगदड़ में मरने वालों में ज्यादातर दलित और गरीब तबके के लोग शामिल हैं पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, घरेलू समस्या और रोजगार नहीं मिलने से होने वाली परेशानियों का समाधान फर्जी बाबाओं के जरिए तलाश किया जाता है। सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार औलालपीताशाही का दमन देश के पिछड़े तबके लिए कोढ़ में खाज सबित हुआ है। इस हालत ने देश में फर्जी बाबाओं को पनपने का मौका दिया है। ज्यादातर बाबाओं की पृष्ठभूमि भी गरीब तबके की रही है। इसी का फायदा जालसाजी करके बाबाओं ने उठाया है। आम लोगों की दुख-तकलीफ जब शासन-प्रशासन से दूर नहीं

भारत में बढ़ता शहरीकरण भल ही विकास का आधार हो, लेकिन इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। बढ़ता शहरीकरण केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिये एक बड़ी चुनौती बन रहा है। वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी में से 56 फीसदी आबादी शहरों में रहने लगी है। गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक शहरी आबादी अपने वर्तमान आकार से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने एवं नया भारत-विकसित भारत बनाने के लिये शहरीकरण पर बल दिया जा रहा है। एक विडम्बनापूर्ण सोच देश के विकास के साथ जुड़ गयी है कि जैसे-जैसे देश विकसित होता जायेगा वैसे-वैसे गांव की संरचना टूटती जायेगी। निश्चित ही जब भी शहरों में कोई नई कॉलोनी विकसित होती है तो हमें यह स्वीकारना ही होगा कि किसी न किसी गांव की कुर्बानी हुई है। एक और विडम्बना एवं त्रासदी है कि जिन्हें शहर कहा जा रहा है वहाँ अपने संसाधनों से वंचित लोगों की बेतरतीब, बेचैन और विस्थापित भीड़ ही होगी। कुछ समय पूर्व स्विट्जरलैंड के दावों में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें यह बात उभर कर सामने आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की भूमि माना जा रहा है। यह सही भी है क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। भारत में नवीन भारत की पहल के विचार को आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढाँचों में सुधार के समग्र ट्रूटिकोण को अपनाये जाने की अपेक्षा है। वैश्वीकरण के उत्परांत शहरी विकास की अवधारणा समावेशी विकास की एक अनिवार्य शर्त बन गई है। शहरी विकास की इस प्रक्रिया ने गाँवों के सापेने अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया है। शहरों का अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश, पर्यावरण की समस्या, बढ़ता प्रदूषण, जल का अभाव एवं शहरी संस्कृति में बढ़ते जा रहे संबंधमूलक तनाव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि शहरी विकास की अवधारणा पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिये। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने में गाँवों की तुलना में शहरों की



नूनका जावक ह, ता बना यह कहा जा सकता ह कि प्रकास और प्रदूषण का एक-दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है? बेहतर रोजगार, आधुनिक जनसुविधाएं और उज्ज्वल भविष्य की लालसा में अपने पुश्टैनी घर-बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन करने की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है कि देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या लगभग 350 हो गई है जबकि 1971 में ऐसे शहर मात्र 151 थे। यही हाल दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरीकरण को विकास का पैमाना माना जाता है। शहरों में गांवों की तुलना में अधिक साधन, सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा दूसरे शब्दों में आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं। यह भी सच है कि ये सुविधाएं सभी का नसीब भी नहीं होती। रोजगार के लिए गांवों से शहरों में आने वाले बहुत सारे लोगों को कच्ची बसियों, चालों या एक से दो करमरे के मकानों में किराए पर रहने को बाध्य होना पड़ता है। शहरों में बुनियादी सुविधाओं के बावजूद सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र पर खासा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। शहरों में रहना दूर ही होता जा रहा है। अपसल में देखें तो संकट वायु प्रदूषण का हो या जंगल का, स्वच्छ वायु का हो या फिर स्वच्छ जल का, सभी के मूल में विकास की वह अवधारणा है जिससे शहर रूपी सुरक्षा सतत विस्तार कर रही है और उसकी चपेट में आर ही है प्रकृति और उसकी नैसर्गिकता। जिसके कारण मनुष्य की सांसारे उलझती जा रही है, जीवन पर संकट मंडरा रहा है। अगर हमें पूरी समस्या से लड़ना है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित महानगरों के स्तर पर और साथ ही पूरे देश के स्तर पर

अपनी कई आदतों को बदलना हांगा, विकास के तथाकथित मॉडल पर गंभीर चिन्तन करना हांगा। वायु प्रदूषण का कारण पराली एवं सङ्कटक पर दौड़ते निजी वाहनों में खाजने की बजाय हमें महानगरों के अनियोजित शहरीकरण में खोजना होगा। पर्यावरण सुरक्षा के महेनजर शहर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं क्योंकि शहर के विकास के लिये हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, विशेषतः सुमुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रह गए हैं। इसके अलावा, तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिये खतरा बन गया है क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियां बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वर्चित हैं। प्रत्येक शहर में बैतरीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में रहने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिये यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सङ्कट हो जाता है। शहर के लिए सङ्कट चाहिए, बिजली चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए और दफ्तर चाहिए। इन सबके लिए या तो खेत होम हो रहे हैं या फिर जंगल। जंगल को हजम करने की चाल में पेड़, जंगली जानवर, पारंपरिक जल स्रोत सभी कुछ नष्ट हो रहा है। यह वह नुकसान है जिसका हर्जाना संभव नहीं है और यही वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। शहरीकरण यानी रफ्तार और रफ्तार का मतलब है वाहन और वाहन है कि विदेशी मुद्रा भंडार से खरीदे गए ईंधन को पी रहे हैं और बदले में दे रहे हैं दूषित वायु। शहर को ज्यादा बिजली चाहिए यानी ज्यादा कोयला जलेगा, ज्यादा परमाणु संयंत्र लगेंगे। शहर का मतलब है औद्योगिकीकरण और अनियोजित कारखानों की स्थापना, जिसका परिणाम है कि हमारी लगभग सभी नदियां अब जहरीली हो चुकी हैं।

आप का

नजरीया

पत्थरों से मिट्टी हलाल

सिया

सियासी बिछाने पर सलवटें हजारों, फिर भी घाट पर चादरें लड़ रहीं। राजनीति कितनी कुत्सित हो सकती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए नेताओं के संबोधन अब अपनी भाषा की पैरवी करते मिलेंगे। लगभग सांगे हुए वक्त पर लाठियां चला कर, कोई है जो देश को जगाने के शोर में खुद है। बहस राष्ट्रीय स्तर पर मोदी बनाम राहुल हो गई तो लोकसभा-विधानसभाओं के कान खुल गए। वक्त पे भरोसा नहीं भविष्य को पोता जा रहा है। दिल्ली के बयान, हिमाचल में उपचुनाव के इम्तिहान में आ कर भिन्न नहीं होते। यहां भी आमना-सामना है और शिक्षण की चाउक में जुबां लंबी है। पूरे उपचुनाव गुजर गए मगर जनता के बूझे होते अरमान कहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें तो लड़ना है सत्ता की दीवारों पर, बस इक यही पैगाम पढ़ना है कि तू दरकिनार होगा तो हम आएंगे। खैर प्रदेश की मिट्टी में तो फसाद न था, उनके पत्थरों ने हलाल कर दिया। उपचुनाव के चरम में राजनीति पर शुरू हुई बहस मौके पे चौका नहीं, बल्कि हम भांप सकते हैं कि ये गलियां यूं ही बदनाम न हुईं। हमीरपुर उपचुनाव ने हमीरपुर की अस्मिता को उपचुनाव बना दिया, तो वक्त के पैमानों ने पूछा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। वैसे यहां आज धूमल का नाम चर्चा है, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश की राजनीति अगर इस सवाल पर कोई दिल्लित हो जाए तो हिमाचल से क्षेत्रवाद की सारी सरहदें मिट जाएं, लेकिन कहने को गालिब यह छ्याल अच्छा है, मगर करने को यह कोई वादा नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खु ने कहा है कि 2017 में धूमल की हार में हमीरपुर हार गया और तकालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस क्षेत्र को सजा देंदी। यानी साजिशों की गोलबदी में तब भी कोई किरदार था जो आज बहरूपिया बन कर फिर से मुख्यमंत्री पद पर बार है। मुख्यमंत्री के तर्क और निष्कर्ष में हमीरपुर पीड़ित व शोषित नजर आता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि अब मुख्यमंत्री का पद एक जिले तक सीमित होने लगा या मंत्री का पद एक विधानसभा क्षेत्र हो गया। ऐसे में विधायक और खासतौर विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा के लिए तो मतदाता ही दोषी हुआ। बेशक संवेदन और उम्मीदों की पालकी में चुनाव परिणाम आते हैं, लेकिन हर मत की ख्वाहिश में लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए। परिस्थितियां उस वक्त जरूर बदली थीं जब मुख्यमंत्री का पद सुजानपुर में हार गया था, लेकिन प्रेम कुमार धूमल को हम केवल हमीरपुर जिला के सियासी नुकसान में मूल्यांकित नहीं कर सकते और यह भी एक सत्य है कि बतौर मुख्यमंत्री हरे तो वीरभद्र सिंह और शांता कुमार भी, लेकिन न कारवां शिमला का रुका और न ही कांगड़ा कहीं थामा। ऐसे में हम तो यह नहीं कहेंगे कि नादौन के विधायक होने के नारे मुख्यमंत्री केवल हमीरपुर के हो गए, बल्कि उन्होंने खुद को कांगड़ा से जोड़ कर यह साबित करने की कोशिश की, फिर भी हिमाचल में राजनीतिक सोच, सरकार की कार्रवाई, मंत्रियों की भूमिका और प्रशासन की मुंह दिखाई, अपने आप में क्षेत्रवाद सी लगती है। विकास कल राजनीतिक नस्ल था, अब हिमाचल को आगे बढ़ने, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर तथा रोजगार देने की रूपरेखा चाहिए।



दूसरा विमेस टी-20 बारिश के कारण बेनतीजा : साउथ अफ्रीका ने 177 रन बनाए, तजमिन ब्रिट्ज की फिफ्टी; वस्त्राकर-दीप्ति को 2-2 विकेट

चेन्नई।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विमेस टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा। चेन्नई में मेहमान टीम ने टीस डारकर पहले बैटिंग की। अपने तजमिन ब्रिट्ज के लिए लोगों के द्वारा दूरी टी-20 में फिफ्टी लगायी। उनकी फिफ्टी के सहारे टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन बना लिए। साउथ अफ्रीका से अनेक बोश ने 32 बॉल पर 40 रन की पारी खेली। भारत से पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। पहली पारी खेल होते ही चेन्नई में बारिश होने लगा। इस कारण भारत की बैटिंग शुरू नहीं हो सकी।

पहला टी-20 जीतने साथ अफ्रीका सीरीज के में 1-0 से आगे है। तीसरा टी-20 मैच 9 जुलाई को चेन्नई में ही खेला जाएगा।

ओपनर्स ने दिलाई तेज शुरूआत - चेपॉक स्ट्रिंग्स में साउथ अफ्रीका को ओपनर्स ने दूसरे टी-20 में देखा गया था। कसान लोगों द्वारा लोड और ब्रिट्ज ने 4 ओवर में 43 रन बना लिया। 19वें ओवर में बोश ने वस्त्राकर को कैच आउट कराया और भारत को पहली सफलता दिलाई। कसान ने 22 रन बनाए।

ब्रिट्ज की लगातार 10 साल से फिफ्टी - पहले टी-20 में 81 रन की मैच विनिंग पारी खेलने वाली ओपनर ब्रिट्ज ने इस मैच में भी

फिफ्टी लगा दी। उन्होंने 39 बॉल पर 52 रन बनाए। उनके सामने मारिजान कैप 14 बॉल में 20 रन बनाकर आउट हुई। दोनों को दीप्ति शर्मा ने परवेलियन भेजा।

अनेक बोश ने 160 पार पहुंचाया स्कोर - 113 रन से करोंगे पर साउथ अफ्रीका को 3 टी-20 की सीरीज खेली जा रही है। तीसरों मैच चेन्नई में है, साउथ अफ्रीका ने पहला मुकाबला 12 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाती थी। दूसरा टी-20 बारिश के कारण बेनतीजा रहा। तीसरा मैच दूसरी बारी नहीं जीता तो टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दूसरी टी-20 सीरीज गंवा दी।

न्यूजीलैंड

एलिंगन, अकिंता ने इस आधार पर ओलंपिक के लिए क्लाइफाई किया भारतीय एथलीटों की संख्या बढ़ी



नई दिल्ली। ऐरिस ओलंपिक को शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और सभी एथलीट इसमें अपना दमखंड दिलाने के लिए तैयार हैं। इस लीवर लंबी कूद के भारतीय एथलीट और 5000 मीटर की दौड़ की धाविका अकिंता श्यामी ने भी ऐरिस ओलंपिक के लिए क्लाइफाई कर लिया है। इन दो एथलीटों ने विवर रेकिंग कोटे के जरिए ऐरिस ओलंपिक के लिए क्लाइफाई कर लिया तो भारतीय एथलेटिक्स टीम में सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 गई है। ऐरिस ओलंपिक की शुरूआत 26 जुलाई से होती है। लंबी कूद के राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स डिल्लन और अकिंता का नाम विश्व एथलेटिक्स (डब्ल्यूएफ) द्वारा प्रकाशित नवीनतम सूची में शामिल है। राष्ट्रीय महासंघ एथलेटिक्स संस्था को अपने उन एथलीटों के बारे में सुनित किया जा कर बनाने के बावजूद विभिन्न कारोंगों से परिस एं प्रतिस्पर्धा नहीं। इसी तरह कहा जाएगा। उन्हें कहा है, ये दोनों विवर रेकिंग के जरिए सुधी में शामिल हो जाएंगे।

अकिंता को 42वें रात पर रखा गया था और अतिम रेकिंग स्टेटमेंट। दो जुलाई को शुरू होने वाले एथलीट को जारी किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स टीम में सोधे एथलीट के बाबत जारी किया गया है। एथलीट को जारी किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एफएआई) के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि दोनों का भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा। उन्हें कहा है, ये दोनों विवर रेकिंग के जरिए सुधी में शामिल हो जाएंगे।

भारतीय एथलेटिक्स टीम 9 और 12 जुलाई को न्यूजीलैंड से खेलेंगी तैरी जैव 23 सदस्यीय टीम घोषित



नई दिल्ली। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम म्यामी के खिलाफ 9 और 12 जुलाई को दो मैच खेलेंगी। इसके लिए 23 सदस्यीय भारतीय महिला फुटबॉल टीम होगी तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सार्वजनिक कर दी गयी है। भारतीय एथलीट टीम को मुख्य लंबी चाल देती है दो दोनों खेलों की लंबी चाल देती है। इसके लिए भारतीय एथलीट और जानियर खिलाड़ियों का मिश्रण है। साथ ही कहा कि टीम का सार्वजनिक अच्छा है। उन्होंने कहा कि पछले महीने उज्ज्वलिक्षण के साथ खेलने के बाबत हमें 10 दिनों के अंदर ही आगा राष्ट्रीय अभ्यास रिहायर शुरू कर दिया था जिसका भी लाभ मिले। इसके लिए एक अच्छा सकेत है। ये सभी खिलाड़ी अब तक अपने अपने नाम किए थे। दिलचस्प बात यह है कि भारत का ओलंपिक में स्वर्ण ब्रेकेट से बाहर हो जाएगा।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम उज्ज्वलिक्षण द्वारा में एक मैच में 0-3 से हार गयी थी जबकि दूसरे मैच में मुकाबला बराबरी पर रहा था।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम उज्ज्वलिक्षण द्वारा में एक मैच में 0-3 से हार गयी थी जबकि दूसरे मैच में मुकाबला बराबरी पर रहा था।

न्यूजीलैंड लीग ने अविनाश साबले ने दिखाया तन, तोड़ा अपना ही राष्ट्रीय स्टीपलचेज रिकॉर्ड

नई दिल्ली। ओलंपिक के लिए क्लाइफाई कर चुके अविनाश साबले ने डायमंड लीग में 8 मिनट और 9.91

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

दिखायंड लीग ने अविनाश साबले ने दिखाया तन, तोड़ा अपना ही राष्ट्रीय स्टीपलचेज रिकॉर्ड

नई दिल्ली। ओलंपिक के लिए क्लाइफाई कर चुके अविनाश साबले ने डायमंड लीग में 8 मिनट और 9.91

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सेकंड का समय लेकर छाता रहा। मासिल करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

</



Government of Assam
Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs

An innovative measure towards ensuring Food Security

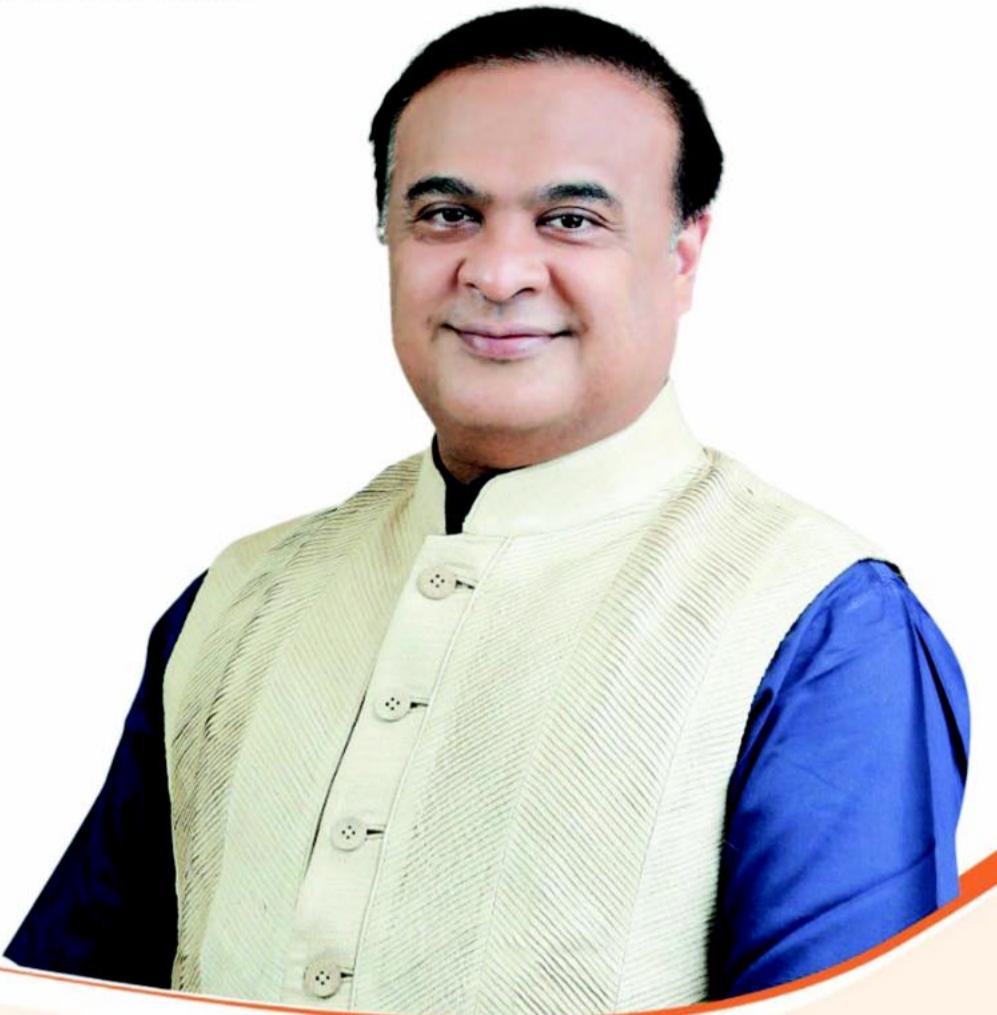
In view of the ongoing flood situation

ANNA SEWA DIN

(July 1-10)

Extended till

15 July 2024



During
these
Special
Days

Under National Food Security Act

For beneficiaries under 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana'

35 kg
rice

Antyodaya Anna Yojana (AY)

Per month, per family

5 kg
rice

Priority Household (PHH)

Per month, per beneficiary

will be provided



Households covered
66,26,421



Beneficiaries covered
2,31,49,341

'To do' for Beneficiaries



Collect free rice from Fair Price Shops
during these days



Collect receipts generated by e-PoS
machines against the rice received



*Collect your entitled rice from
the concerned Fair Price Shop through
e-PoS devices*



Mandatorily inform beneficiaries about
Anna Sewa Din through wide publicity



Keep the shop open throughout the day
during Anna Sewa Din



Ensure full distribution of rice entitled to
beneficiaries during Anna Sewa Din



Produce receipts of e-PoS machines against
rice received by the beneficiaries

If any beneficiary does not receive due quantity of free rice



Contact 1800-345-3611 | 1967

(toll free) between **9 AM to 6 PM**

-- Janasanyog /D/2271/24/9-Jul-24